प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

07 अगस्त 2018

2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 14 - रक्षा सेवाएं, वायुसेना संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 – रक्षा सेवाएं, वायुसेना संसद के दोनों सदनों में आज प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवेदन के संबंध में

यह प्रतिवेदन भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के वित्तीय लेन-देन तथा आईएएफ से संबंधित रक्षामंत्रालय (एमओडी), रक्षालेखा विभाग (डीएडी), सैन्य अभियान्त्रिकी सेवायें (एमईएस) तथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन और आईएएफ की प्राथमिकता को समर्पित इसकी प्रयोगशालाओं में मौजूद अभिलेखों की लेखापरीक्षा से उद्भूत मामलों से संबंधित है। प्रतिवेदन में शामिल किए गए मुख्य निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गई है:-

Chapter 1 - I स्वदेशी वायु-वाहित पूर्व चेतावनी एंव नियंत्रण सिस्टम (एईडब्ल्यू एवं सीएस) का विकास

एईडब्ल्यू एवं सी प्रणाली के स्वदेशी विकास हेतु परियोजना 2011 तक पूरी की जाने के लिए ₹1800 करोड़ की लागत पर 2004 में अनुमोदित की गई। आईएएफ द्वारा निर्दिष्ट कुछ परिचालनात्मक आवश्यकताओं की अप्राप्ति के अतिरिक्त, 70 प्रतिशत अतिरिक्त समय लगा था। एम्ब्रेअर के प्लेटफार्म के रूप में चयन ने डिजाइन संबंधी अवरोध उत्पन्न किये तथा विलंब का कारण बना। स्वदेशीकरण की उपलब्धि परियोजना लागत की लगभग 48 प्रतिशत मात्र थी। 2002 में कल्पित परियोजना को अभी भी पूरी तरह से वास्तविक रूप दिया जाना बाकी है, जिससे आईएएफ के हवाई सर्वेक्षण क्षमता में कमी रह गई है।

(पैराग्राफ 2.1)

Chapter 2 - II मिग वायुयान टायरों की अधिप्राप्ति में अनियमितता

त्रुटिपूर्ण निविदा प्रक्रिया जो कि 2009 से अपनाई गई, ने सुनिश्चित किया कि अनुबंध एक ही विदेशी विक्रेता को बार-बार दिया जा सके, बावजूद इसके कि विक्रेता खराब टायरों की आपूर्ति कर रहा था। फर्म द्वारा ₹ 5.92 करोड़ मूल्य के खराब, अनुपयोगी 3080 मिग टायर आईएएफ पर थोपे गए हैं। त्रुटिपूर्ण आरएफपी जारी की गई जब कि यह ओआर एवं कीमत मूल्यांकन मापदण्ड को सही रूप से वर्णित नहीं करती थी। विक्रेताओं का आरएफपी जारी करने के लिए चयन छांट तथा पसंद के आधार पर किया गया। टायरों के आयात को आसान बनाने के लिए स्वदेशीकरण का परित्याग कर दिया गया। **(पैराग्राफ 2.2)**

Chapter 3 - III एमआई-17 1V हेलीकॉप्टरों की मरम्मत तथा ओवरहॉल हेतु निविदा में अनियमितता

आईएएफ ने अनुपयुक्त रूप से एमआई-171V हेलीकॉप्टरों के लिये मरम्मत और ओवरहॉल की सुविधा की अधिप्राप्ति में देरी की। हेलीकॉप्टरों की मरम्मत और ओवरहॉल को गंभीर विलंब, अधिक व्यय और रशियन फर्म द्वारा हेलिकॉप्टरों की मरम्मत और ओवरहॉल के एकाधिकार का सामना करना पड़ा। जब तक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये, अधिकांश हेलीकॉप्टर मरम्मत के अभाव में ग्राउंडेड थे। आरओएच सुविधा की स्थापना जिसकी लागत लगभग ₹ 196 करोड़ होती, न करने से, आईएएफ द्वारा हेलीकॉप्टरों को मरम्मत के लिए विदेश में भेजने के फलस्वरूप लगभग ₹ 600 करोड़ का व्यय तय था।

(पैराग्राफ 2.4)

Chapter 4 - IV भारतीय वायु सेना एयरफील्डों की परिचालनात्मक तत्परता

एयरफील्डों की परिचालनात्मक तत्परता हवाई परिचालनों हेतु, विशेष रूप से युद्ध के दौरान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा में आईएएफ एयरफील्डों में सहयोगी सुविधाओं में कमियाँ पाई जिसने उनकी तत्परता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इनमें बमबारी के बाद रनवे का पुननिर्माण, संचार प्रणालियों का आधुनिकीकरण, वायुयान की सुरक्षित लैंडिंग तथा टेक-ऑफ, वायु में रहते हुए वायुयान का सर्वेक्षण, वायुयान का पुन:ईंधनीकरण तथा वायुयान पर लादने जाने वाले हथियारों व गोला-बारूद का रखरखाव जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। भारत सरकार (जीओआई) ने 2014 तक 'केके' एयरफील्डों के आधुनिकीकरण हेतु ₹ 1220 करोड़ की लागत पर एयरफील्ड आधारिक अवसंरचना के आधुनिकीकरण (एमएएफआई) हेतु परियोजना क्रियान्वित की। अब तक केवल कुल 'एमएम' एयरफील्ड कमीशन हुए थे। एयरफील्डों द्वारा अधिकृत उपस्कर में कमी थीं, जो मुख्य रूप से अधिप्राप्ति में विलंब के कारण था।

(पैराग्राफ 3)